ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 185-188
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सतत विकास : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

सोनी देवी

शोध अध्येत्री– समाजशास्त्र, सी०एस०जे० एम० कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर (उ0प्र0), भारत

Received-19.05.2023, Revised-25.05.2023, Accepted-29.05.2023 E-mail: sonidevi273@gmail.com

सारांशः ***एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर से मजबूत बनाना है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना से आशय 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता उपलब्ध कराना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा "2 अक्टूबर 1975" को भारत में "एकीकृत बाल विकास सेवा योजना" का प्रारंभ किया। स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय" अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । इससे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की गति को बढ़ाकर महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य कुपोषण, विकलांगता, रुग्णता, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को समाप्त किया जा सकेगा, और उन्हें शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर से मजबूत बनाया जा सकेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान कर उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सकेगा। यह योजना बच्चों और महिलाओं के विकास और स्वास्थ्य को देखते हुए उपयुक्त साबित हुई है। इस योजना को अत्यंत लोकप्रिय बनाना होगा जिससे आज के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार कर कल के भारत को संवारा जा सकेगा।***

कुंजीभूत शब्द– एकीकृत बाल विकास, सतत विकास, स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक स्तर, गर्भवती महिलाओं।

इस योजना के प्रमुख 5 उद्देश्य निम्नलिखित हैं– 1. 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। 2. बच्चों का समुचित, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक ,सामाजिक विकास करना है। 3. बाल मृत्यु दर, अस्वस्थता, कुपोषण ,और स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना है। 4. बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में कारगर तालमेल स्थापित करना है 5. बच्चों के स्वास्थ्य व देखरेख के लिए माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर उनकी क्षमता को बढ़ाना है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत 6 प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाती हैं :– 1. अनुपूरक पोषण 2. पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा 3. स्कूली शिक्षा से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा 4. प्रतिरक्षण 5. स्वास्थ्य जांच 6. रेफरल सुविधा।

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है, परंतु इसके कुछ घटक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भी संचालित किए जाते हैं।

सतत विकास क्या है ?– ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती हैं और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। पहली बार सतत विकास शब्द संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा पर्यावरण और विकास पर 1987 में परिभाषित किया गया था।

समावेशी विकास में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का सामाजिक दृष्टिकोण– भारत में चहुमुखी विकास हुआ है, परंतु महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आज भी समस्या देखने को मिल रही है। विश्व भर में भारत सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है, लेकिन मानव विकास का आर्थिक विकास से कोई खास तालमेल नहीं है। भारत में अभी भी लगभग 22% बच्चे गरीबी में रहते हैं। उन्हें उचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है जिसके कारण उन्हें कुपोषण, अस्वस्थता, विकलांगता और रुग्णता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2016 की मानव विकास रिपोर्ट में 188 देशों में से भारत का 131 वां स्थान था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, कुपोषण, गुणवत्ता परक स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता की कमी, शुद्ध पेयजल आज भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। सभी को भेदभाव किए बिना समान रूप से स्वास्थ्य को देखते हुए पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल, और समान शिक्षा आदि को सतत विकास के माध्यम से लाभान्वित कराना है। समावेशी विकास पर यूनिसेफ का कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा के साथ चल रहा है। जो न्यायिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चों और महिलाओं को समान रूप से लाभान्वित कर रहा है। यूनिसेफ समावेशी विकास ने सामाजिक रूप से सार्थक साबित हुआ है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना द्वारा बच्चों को समान रूप से पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है और उन्हें समान रूप से अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सतत विकास के लक्ष्यों के साथ मिलकर बच्चों और महिलाओं के विकास में समान रूप से भूमिका निभा रही है। ताकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। अतः यह योजना अत्यधिक सार्थक सिद्ध हुई है।

गरीबी उन्मूलन में सहायक– भारत ने चरम गरीबी को बहुत अधिक कम कर दिया है जिससे हम सभी अवगत हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 तक गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना है। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत जिन गरीब बच्चों को और उनकी माताओं को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। उन्हें राज्य सरकार ने पोषक आहार प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की है। जिससे गरीब बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक आहार मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गरीबी की वजह से लाखों बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। गरीबी निरंतर विनाश और परिवर्तन पर्यावरण में रहते हैं। यह शांति और न्याय से संबंधित हैं। गरीबी उन्मूलन एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।1.2 बिलियन लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी को कम करने के लिए खाद्य आपूर्ति में वृद्धि कर समाप्त किया जा सकता है। 2030 तक गरीबी को कम करके असमानताओ को कम करने पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

और पोषण स्तर में सुधार करके गरीबी को कम किया जाना है। बेहतर खाद्य सुरक्षा से गरीबी को कम किया जा सकता है। जिससे एकीकृत बाल विकास योजना के द्वारा उन गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना गरीबी उन्मूलन में भी सहायक सिद्ध हुई है।

भुखमरी की समाप्ति– संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 तक एनीमिया से पीड़ित बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं की संख्या को कम करके 23.57 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। किंतु भारत आज इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। भोजन मे आयोडीन की कमी के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न हुई जिससे स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर उन्हें आयोडीन युक्त नमक प्रयोग करने और उनके लाभ के बारे में बताना है ताकि बच्चों का शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास भली–भांति हो सके। से होने वाली आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण की स्थापना की गई है। फिर भी यह लक्ष्यअभी 50.30% ही पहुंच पाया है। बिहार त्रिपुरा मेघालय जैसे राज्य आज भी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है। 5 साल के बच्चों में 21.3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे एकीकृत बाल विकास सेवा के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर एनीमिया जनित रोगों से छुटकारा देने में सहायक है। बच्चों की लम्बाई में भी सर्वाधिक समस्या देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश 46.3% बच्चें स्टंटिंग से प्रभावित हैं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और आयरन से युक्त गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराकर भुखमरी जैसी समस्या को समाप्त करने में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सहयोग प्रदान करने का कार्य कर रही है।

अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन– जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक खुशहाल जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। सतत विकास का लक्ष्य का उद्देश्य 2030 तक सभी बच्चों को कुपोषण मुक्त करना है और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है ताकि बच्चे खुशहाल और अच्छा जीवन जी सकें। सतत विकास में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अपनी विशेष भूमिका निभा रही है। बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने से उनके स्वास्थ्य में मैं बदलाव आया है। 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है तथा 2030 तक शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को 1000 से कम से कम 25 तक लाना है। सभी को समान रूप से सेवाएं उपलब्ध कराकर उनके स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीने में योगदान कर रहा है अतः इस प्रकार बाल विकास सेवा योजना सतत विकास लक्ष्य में अहम भूमिका निभा रही हैं।

सभी वर्ग के बच्चों और महिलाओं को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना– वर्ष 2030 तक सभी के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा का लक्ष्य है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सतत विकास लक्ष्य के तहत सभी वर्ग के बच्चों और महिलाओं को गुणवत्ता परक और अनौपचारिक शिक्षा देना होगा। जो कि बच्चों के ज्ञान के निर्माण के लिए आवश्यक है। हर वर्ग की महिलाओं को समान रूप से स्वास्थ्य के प्रति शिक्षा प्रदान करना है स जो कि बच्चों ज्ञान के निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण है है ताकि बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। विकास शिक्षा सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण पहलुओं को कवर करती है शिक्षा समाज के लोगों में प्रतिभा ज्ञान और अनुभव को पोषित करने में मदद करती है वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा को वैश्विक चुनौतियों को जवाब देने के तरीके से ज्ञान प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए ज्ञान प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का पता लगाकर बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का पता लगाकर उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। जिसमें एकीकृत बाल विकास सेवा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रही है।यूनिसेफ ने global generation unlimited साझेदारी शुरू की है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2030 तक सभी बच्चे स्कूल जाएं ताकि वे अपने लक्ष्य हासिल कर एक अच्छा नागरिक बन सकें।

लैंगिक समानता और कुपोषण– लैंगिक समानता स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पौष्टिक आहार से और खाद्य पोषण सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना से जहां बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार किया जाता है वहीं महिलाओं और पुरुषों के बीच खाद्य सुरक्षा में बहुत अंतर पाया जाता है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 828 मिलियन लोग प्रभावित हैं जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। जहां पर लैंगिक असमानता सबसे अधिक होगी वहां उतने ही लोग अस्वस्थ और कुपोषित होंगे। यमन सिएरा लियोन जैसे उच्च लैंगिक समानता वाले राष्ट्रों में पोषण और अस्वस्थता का अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार महिलाओं को समान रूप से पौष्टिक आहार खाद्य पोषण सहायता उपलब्ध कराकर एकीकृत बाल विकास योजना सतत विकास लक्ष्य में विशेष भूमिका निभाने का कार्य कर रही है।

स्वच्छ जल और स्वच्छता– एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सतत विकास लक्ष्य के साथ पूर्ण रूप से कार्य कर रही है प्रत्येक बच्चे को साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए भारत में खुले में शौच को समाप्त करने में तेजी से प्रगति हुई है। 2019 से भारत में गरीब और असहाय लोगों को जंगलों में निवास करने वाले, खुले में शौच करने वाली संख्या में कमी आई है। खुले में शौच करने से गरीब बच्चों में डायरिया और जल जनित बीमारियों का खतरा रहता है इसकी वजह से भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 100,0000 बच्चों की डायरिया से मौत हो गई थी। भारत में अपर्याप्त पानी और स्वच्छता सेवाएं नवजात मृत्युदर में योगदान करती हैं। वर्तमान में 1000 पर 24 मौतें हैं जो नवजात मृत्युदर का 15% और मातृ मृत्यु दर का 11% योगदान देता है। यूनिसेफ पेयजल और स्वच्छता में अपना योगदान दे रहा है। जिससे बच्चों को शुद्ध पानी स्वच्छ और स्वस्थ रखा जा सके। इस प्रकार एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य के साथ काम कर रही हैं।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृण बनाना– IAEA देशों के विकास के लिए ऊर्जा की मांग को पूरा करने में सतत विकास लक्ष्य मदद करता है। पर्यावरण स्वास्थ्य पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव की दृष्टि से काम करने में मदद करता है ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर बिजली की आपूर्ति एक चुनौती बनी हुई है। 2017 के आंकड़े के अनुसार 4.6% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिजली आपूर्ति नहीं थी। 2021 के 2021 के अध्ययन से पता चलता है कि स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली आपूर्ति की कमी 64 प्रतिशत कम प्रसव होने से जुड़ी है जो महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करती है ऐसी स्थिति में ऊर्जा आपूर्ति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके ग्रामीण अस्पतालों को और सशक्त बनाया जा रहा है अतः सतत विकास लक्ष्य और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के एक दूसरे के साथ कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य– जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ रहा है हमारा स्वास्थ्य पारितंत्र के गुणवत्ता पर निर्धारित है पर्यावरण और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को सक्रिय रूप से गति प्रदान कर रही है, फिर भी जलवायु परिवर्तन और वैश्विक आपूर्ति चिंता का विषय है भारत सरकार बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के पूरक पोषण टेक होम राशन प्रदान करती है।

जलवायु परिवर्तन से होने वाली कोविड–19 जैसी महामारी बीमारियों से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ने दरवाजे पर सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाया है कुपोषण को समाप्त करने के लिए पर्याप्त सुधार किया जा रहा हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 93: बच्चे वायु प्रदूषण में सांस लेते हैं जो उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए एक बड़ा जोखिम है भारत के लिए और अधिक चिंता का विषय है 2019 के अनुसार 21% बच्चे प्रदूषित शहरों में रहते हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से लगभग 50% बच्चे हीटवेव से प्रभावित हैं। Only My Health रिपोर्ट के अनुसार– जलवायु परिवर्तन और तेजी से फैलते हुए प्रदूषण में सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों के विकलांग होने का खतरा है। यह सबसे ज्यादा बच्चों के शारीरिक और जीवित रहने के लिए सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा बच्चों पर ही खतरा दिख रहा है क्योंकि बच्चों का शरीर विकास की ओर अग्रसर होता है जो बहुत संवेदनशील समय होता है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सतत विकास लक्ष्यों के साथ मिलकर बच्चों को जलवायु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों से निजात दिलाने के लिए स्वास्थ्य जांच करा कर और टीकाकरण आदि सेवाएं प्रदान कर सतत विकास लक्ष्यों के साथ काम कर रही हैं। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित सतत विकास लक्ष्यों में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अपनी भूमिका निभा रही है।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सतत विकास में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण– एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत सतत विकास लक्ष्यों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से समाज में बच्चों और महिलाओं को सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में सामने उभर कर आई है जो महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को चिन्हित करती है और पोषण सहायता प्रदान करने के प्रति सक्रिय है भविष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थात सतत विकास को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विकास में सतत भूमिका निभा रही है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत गरीबी, भुखमरी कुपोषण लैंगिक असमानता शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जलवायु परिवर्तन आदि संतुलित विकास में सामाजिक दृष्टि से पूरा करने में सक्षम है।

स्वास्थ्य के साथ बेहतर मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य प्राप्त सेवाएं रुग्णता के उपचार और मृत्यु दर में कमी लाने के बारे में शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है यह पोषण पर गैरऔपचारिक शिक्षा में भी शामिल होने का समान रूप से अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य, पोषण, गरीबी, मनोरंजन, को एकीकृत बाल विकास योजना में शामिल किया गया है। जिससे बच्चों के शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्तर से मजबूत बनाया जा रहा है।

यूनिसेफ भी बच्चों के सामाजिक विकास को बढ़ाने और सभी बच्चों को न्याय संगत दृष्टिकोण के साथ प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान देता है यूनिसेफ आने वाली पीढ़ियों के भविष्य अर्थात् सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रहा है। महिलाओं और बच्चों के सामाजिक स्तर से मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यूनिसेफ बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता, के लिए सतत विकास में समर्थन कर रहा है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और यूनिसेफ दोनों मिलकर बच्चों के लिए सामाजिक और शारीरिक मानसिक और शैक्षिक स्तर पर विकास कर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्युदर में कमी को कम कर रहा है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना संपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण से एक आदर्श बदलाव किया है।

शोध प्रारूप– प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है जिसमें समस्या से संबंधित घटनाओं और उनके प्रभावों पर विचार किया जाता है।

निष्कर्ष– स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना सतत विकास के लक्ष्य और उनके उद्देश्यों की दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ रही है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना द्वारा किया जा रहा विकास वर्तमान में और आने वाली पीढ़ियों के लिए शारीरिक मानसिक शैक्षिक और सामाजिक स्तर से मजबूत बनाने में मदद करेगी गरीबी शुद्ध पेयजल स्वच्छता असमानता जैसी समस्याओं को कम करने में सराहनीय कार्य कर रही है। फिर भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि अन्य योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया जा सकता है अन्य योजनाओं के माध्यम से भी सतत विकास के लक्ष्यों

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

को प्राप्त किया जा सकता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ लगातार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य योजनाओं को सक्रिय करने का काम कर रहा है। इस प्रकार एकीकृत बाल विकास सेवा योजना लगातार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभा रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. रंजन, ज्ञान – 2021, पहल –निदेशालय बाल एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ स
2. अग्रवाल, एम. के.– 2007, उत्तर प्रदेश में विकास योजना, पब्लिकेशन राधा कमल नई दिल्ली।
3. हुड्डा, बी. एस– 2004 – विकास की उड़ान अभी बाकी है, वाणी पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4. खुराना, ललिता – 2022– ग्रामीण विकास मे ई गवर्नेंस, दिसंबर, कुरुक्षेत्र।
5. खुराना, ललिता – 2023 – अक्षय संसाधन, फरवरी, कुरू क्षेत्र।
6. हिंदुस्तान समाचार पत्र– 17 सितंबर 2022– शिक्षा स्वास्थ्य आदर्श समाज की आधारशिला।
7. नीतियां योजनाएं और कार्यक्रम का एक विहंगावलोकन– 2022, मुद्रक कोर प्रयागराज पब्लिकेशन।
8. गुप्ता, प्रोफेसर एस.पी –2022 –अनुसंधान संदर्शिका, शारदा भवन पब्लिकेशंस प्रयागराज।
9. आहूजा, राम – सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
10. www.edurev.in
11. www.unicef.org.

*****